Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 7, December-2021, ISSN 2230-7540

छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं और उरांवों के बीच राजनीतिक परिवर्तन की गतिशीलता पर एक अध्ययन

सबिता कुमारी[1*], डॉ. अमृता सिंह[2]

सार *- यह अध्ययन छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं और उरांवों के बीच राजनीतिक विकास की जांच करने का प्रयास करता है, जो इस मुद्दे पर मौजूदा ऐतिहासिक अध्ययनों के बहुमत में दुख की बात है। पिछले अधिकांश ऐतिहासिक अध्ययनों ने आदिवासी राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रमुख राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। उदाहरण के लिए, यदि आदिवासियों का एक समूह ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया, तो अधिकांश शोधकर्ताओं ने ईसाई मिशनरियों को श्रेय दिया या उनकी निंदा की, लेकिन कुछ विद्वानों ने यह समझाने का प्रयास किया है कि आदिवासियों ने ऐसा क्यों किया। ईसाई धर्म अपनाने से पहले उनके विचार क्या थे? उन्होंने अपने दुखों को कम करने के लिए ईसाई धर्म का उपयोग कैसे किया? उन्होंने भूतों और जादू टोना की पूजा का विरोध किया, जो आदिवासियों और हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ईसाई के रूप में लोकप्रिय थे। इस निंदा और बाद की निंदा ने उन्हें खुशी की एक बड़ी भावना प्रदान की क्योंकि इन मान्यताओं को छोड़ना हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, उनकी शक्ति को चुनौती देना।*

----------X----------

1. परिचय

1.1. सामान्य अवलोकन

भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक काल की शुरुआत के बाद से गैर-आदिवासियों द्वारा दिए गए विभिन्न राजनीतिक रूप से प्रेरित नामों का उपयोग करके आदिवासियों की पहचान की गई है। वैदिक साहित्य में, उनका उल्लेख असुरों के रूप में किया गया था, जबकि बाद के ब्राह्मणवादी स्रोतों ने उन्हें राक्षस कहा था। समकालीन लोकप्रिय संस्कृति में भी यह सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जारी रहा। द मैसेंजर ऑफ गॉड जैसी बॉलीवुड फिल्में एक आदिवासी समाज के प्रति गैर-आदिवासी आबादी की धारणा को दर्शाती हैं जहां उन्हें राक्षसों के रूप में चित्रित किया गया था। दुर्भाग्य से, इसी तरह की तर्ज पर बनी एक प्रमुख बॉक्स-ऑफिस हिट, बाहुबली को 2015 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह दर्शाता है कि लोकप्रिय कल्पना में इस धारणा को समय के साथ कैसे वैध किया गया है। "असभ्य" के लिए कठबोली के रूप में जंगल शब्द का सामान्य उपयोग सांस्कृतिक रूढ़िवाद और "प्रमुख" आबादी के नस्लवाद पर प्रकाश डालता है जो मानते हैं कि वे सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ और "सभ्य" हैं। सदियों से यह माना जाता रहा है कि आदिवासी संस्कृति में नैतिकता, नैतिकता और मूल्य नहीं हैं। मूल रूप से, इन लोगों को सिर शिकारी, नरभक्षी और बर्बर के रूप में देखा जाता था, और इस तरह, "बड़े समाज का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य"।

आदिवासियों के "असभ्य" के रूप में चित्रण को औपनिवेशिक कानूनों द्वारा वैध या औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। **18XXXVII** अधिनियम की प्रस्तावना में, संथालों का उल्लेख "संथाल नामक लोगों की असभ्य जाति" के रूप में किया गया था। दुर्भाग्य से, यह पूर्वाग्रह उत्तर-औपनिवेशिक भारत की संविधान-निर्माण प्रक्रिया में जारी रहा। भारतीय संविधान के "पिता" और भारतीय समाज के उत्पीड़ित वर्गों के "मसीहा" ने जोर देकर कहा कि जाति-आधारित ब्राह्मणवादी हिंदू समाज भारत की आदिवासी आबादी को "सभ्य" करने में विफल रहा है, और इसलिए वे "जंगली" के रूप में बने रहे। "तर्कहीन" और बहुत बार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। इस कारण से, उन्हें भविष्य के संविधान के बारे में विचार-विमर्श से बाहर करना उचित और वैध था। अम्बेडकर ने आदिवासियों को नीति-निर्माण प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास किया और सोचा कि वे लोकतंत्र या नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से बाहर रखा जाना चाहिए। उनका विचार था कि "असभ्य" लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हैरानी की बात है कि वह व्यक्ति जो स्वयं सामाजिक भेदभाव का शिकार था, समाज के समान रूप से उत्पीड़ित वर्ग के खिलाफ ऐसी राय रखता था।

उत्पीड़कों ने "अन्य" के उत्थान के बहाने सभ्यता को अपने आर्थिक शोषण को वैध बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित किया। आदिवासियों की भूमि और आर्थिक संसाधनों के अपने अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए वैदिक लोगों ने आदिवासियों को असुर कहा। यह सिद्धांत उत्तर-औपनिवेशिक काल में भी लागू किया गया था जब भारत सरकार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों को "मुख्यधारा" में "सभ्य" करने का प्रयास किया था। विकास के बहाने उन्हें आदिवासियों की निर्वाह अर्थव्यवस्था के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार मिला।

जबकि औपनिवेशिक काल में आदिवासी शब्द का प्रयोग आदिवासियों की पहचान के लिए किया जाता था; स्वतंत्र भारत में, नामकरण में थोड़े से बदलाव के बाद, उन्हें आधिकारिक तौर

www.ignited.in

पर अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, दोनों शर्तें आदिवासियों के अपनी जमीन पर दावे को पुष्ट नहीं करती हैं। हमने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जमीन के मूल निवासियों को संबोधित करने के लिए किया है। यह एक राजनीतिक शब्दावली है जो आदिवासियों के मूल निवासियों के रूप में भूमि और जंगलों पर आदिवासियों के मौलिक अधिकारों को सही ठहराती है। आदिवासी का शाब्दिक अनुवाद एक मूल निवासी या पहले लोग हैं जिन्होंने कुंवारी भूमि को साफ किया और इसे खेती योग्य बनाया। आदिवासी हमेशा यही दावा करते हैं। आदिवासी शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1938 में आदिवासी महासभा द्वारा भूमि पर अपने पैतृक अधिकारों को राजनीतिक रूप से सही ठहराने के लिए किया गया था।

1.2. प्राथमिक स्रोत

इस शोध के लिए जिन प्राथमिक स्रोतों का उल्लेख किया गया है, उन्हें पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

पहली महत्वपूर्ण श्रेणी में 1915-1945 के बीच छोटानागपुर क्षेत्र की आधिकारिक रिपोर्ट (खुफिया, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, आदि) शामिल हैं। इस श्रेणी में कुछ रिपोर्टों को अब तक इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों द्वारा उपेक्षित किया गया है। हालांकि, अपने स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदिवासी पहचान में हेरफेर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के उद्देश्यों के बारे में उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह ईसाई और हिंदू मिशनरियों के प्रति प्रशासन के रवैये या स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं का मुकाबला करने के लिए आदिवासी पहचान का उपयोग करने के उनके प्रयास में देखा जा सकता है। इन रिपोर्टों में क्षेत्र में होने वाली कुछ घटनाओं के उपाख्यानात्मक संदर्भ भी शामिल हैं जो मिशनरियों और आदिवासियों दोनों के कार्यों के संबंध में उनके उद्देश्यों पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं।

स्वतंत्रता के बाद के आधिकारिक रिकॉर्ड में जनगणना रिपोर्ट, योजना आयोग की रिपोर्ट, ढेबर आयोग की रिपोर्ट, भूरिया आयोग की रिपोर्ट और अन्य शामिल हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान करती हैं। रिपोर्ट प्रवास, गरीबी, विस्थापन और प्रतिरोध जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से भी निपटती है।

प्राथमिक स्रोतों की दूसरी श्रेणी में हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे विभिन्न संगठनों के सम्मेलनों और बैठकों की कार्यवाही की रिपोर्ट शामिल है। इनका उपयोग आदिवासी पहचान को बदलने के लिए इन संगठनों के उद्देश्यों और ऐसा करने में वास्तविक सफलता की सीमा का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। दूसरी ओर, आदिवासी संगठनों जैसे उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी और उसके गुट समूहों की बैठकों की रिपोर्ट इस क्षेत्र में आदिवासी राजनीति से संबंधित कुछ मुख्य मुद्दों को उजागर करती है।

स्रोतों की तीसरी श्रेणी में द सर्चलाइट, द बिहार या बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन, और अन्य जैसे समाचार पत्रों की कुछ रिपोर्टें शामिल हैं। ये अभिलेखागार क्षेत्र के आदिवासी संगठनों की राजनीति को समझने के लिए बहुत उपयोगी थे। उन्होंने अपने राजनीतिक संदर्भ और मांगों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की।

चौथी श्रेणी में गांधी, जवाहर लाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वेरियर एल्विन के निजी कागजात शामिल हैं। इन राष्ट्रीय नेताओं के पत्रों ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक शिकायतों के प्रति गैर-आदिवासी नेताओं के दृष्टिकोण, धारणा और दृष्टिकोण को समझने में मदद की।

अन्त में, उरांव के लोक गीतों का प्राथमिक स्रोतों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें आदिवासियों की उनकी पहचान और समय के साथ उनके परिवर्तन के बारे में उनकी आत्म-धारणा की प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। अब तक, इन गीतों का उपयोग केवल प्रसिद्ध मानवविज्ञानी एस.सी. रॉय और अभिक घोष द्वारा उरांव के सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। हालाँकि, इस शोध में, उनका उपयोग दूसरे अध्याय में आदिवासियों के बीच राजनीतिक चेतना के विकास का पता लगाने के लिए किया गया है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेंडे से बिल्कुल अलग है।

1.3. माध्यमिक साहित्य का सर्वेक्षण

इस शोध में जिन मुद्दों पर विचार किया गया है, उनके संदर्भ में माध्यमिक साहित्य का विश्लेषण नीचे दिया गया है। जहां तक परिभाषा का संबंध है, हाल के शोधों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि " आदिवासी" और " आदिवासी" जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियां क्या हैं।

तनिका सरकार, अपनी कृति " व्यू फ्रॉम द फील्ड: एन आफ्टरवर्ड" में, "आदिवासियों" के नामकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। वह कहती हैं कि अब यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि यह औपनिवेशिक आधुनिकता थी जिसने "आदिवासियों" की श्रेणी का निर्माण किया; और यह कि उनके समाज एक सामान्य नाम धारण करने के लिए बहुत विविध और पदानुक्रमित हैं। फिर क्यों इतिहासकार और आदिवासी समान रूप से एक एकीकृत रूब्रिक के विचार पर अड़े हुए हैं - विविधता की आत्म-जागरूकता सामान्य पहचान के दावे के साथ कैसे काम करती है? इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हालाँकि, यह " आदिवासी" विषय को आधुनिकता से बाहर रखता है, न केवल अस्थायीता के संदर्भ में बल्कि स्थानिकता के संदर्भ में भी। सरकार इस विविधता को देखते हुए, "आदिवासियों" की स्थिति से भी पूछताछ करती है, जो जंगलों और पहाड़ियों के अपने अनुमानित स्थान से बाहर चले गए, उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर जो कुछ सदियों से अपने पारंपरिक तह से बाहर रहे हैं। प्रथम बनर्जी ने अपने लेख, "आदिवासी लेखन: कुछ ऐतिहासिक नोट्स" में तर्क दिया है कि जनजाति के विचार का निर्माण "मध्यम वर्ग वाम बौद्धिक" द्वारा

www.ignited.in

किया गया है जितना कि साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किया गया है, कि "आदिवासी" हमेशा के अधीन रहे हैं एक नृवंशविज्ञान टकटकी और ऐतिहासिक समय के बाहर। उनका तर्क है कि "आदिवासियों" में उपसर्ग "आदि" ने समुदाय को "आदि-हिंदू" या "आदि-द्रविड़ियन" जैसे इतिहास पर किसी प्रकार का दावा दिया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से, "आदिवासी" शब्द ही एकमात्र ऐसा शब्द है। उपसर्ग "आदि" के साथ शब्द जो इतिहास के दायरे से बाहर रहता है। वह बताती हैं कि कैसे आदिवासी एक ऐसी संस्था रहे हैं, जिस पर हिंदू और ईसाई धर्म का विवाद और दावा सदियों से चला आ रहा है। बनर्जी ने दलित इतिहासलेखन की तुलना आदिवासी से की और दिखाया कि कैसे चुप्पी और पहचान के दावे को पढ़ने से दलित इतिहास में एक विकास हुआ है, जबकि भारत में आदिवासी इतिहास अभी भी काफी हद तक नव-औपनिवेशिक नृविज्ञान का विषय बना हुआ है।

अशोक कुमार सेन ने अपने लेख "कोलोनियल सिंहभूम में हो सोशल प्रोटेस्ट के बदलते तौर-तरीके" में झारखंड में आदिवासियों के आधुनिक इतिहास को चित्रित किया है और 2000 में इस राज्य के गठन के लिए सात दशक के लंबे संघर्ष को चित्रित किया है। वह दर्शाता है कि किस तरह का प्रतिरोध औपनिवेशिक काल में आदिवासी इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए अब एक रैली स्थल बन गए हैं। सेन आदिवासियों को "अन्य" करने के लिए औपनिवेशिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति की आलोचना करते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि इतिहास अभी बन रहा है, और इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि मौखिकता से साक्षरता की ओर छलांग एक बड़ा कदम रहा है; उदाहरण के लिए, हो आदिवासी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। जबकि ऐतिहासिक रूप से उग्रवाद प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ी आदिवासी पहचान का हिस्सा बना हुआ है, यह इस दावे के नए रूप हैं जिन्हें इतिहासकारों द्वारा जांच की आवश्यकता है।

अपने निबंध, "आदिवासियों, जनजातियों और अन्य नवविज्ञान पूर्व-औपनिवेशिक अतीत को मिटाने के लिए: पूर्वोत्तर भारत से एक उदाहरण" में, इंद्राणी चटर्जी का तर्क है कि पूर्वोत्तर भारत में "आदिवासियों" के बारे में अधिकांश उत्तर-औपनिवेशिक छात्रवृत्ति "अन्य" के निर्माण के औपनिवेशिक विचारों पर आधारित है। "क्षेत्र के वास्तविक संदर्भ में आए बिना, और उन तरीकों की अवहेलना करके जिनमें बौद्ध, बॉन और शैव तांत्रिक, वैष्णव और सूफियों ने असम की कल्पना की थी। वह दीपेश चक्रवर्ती के काम को भी संदर्भित करती है, जो कहते हैं कि अधिकांश उत्तर औपनिवेशिक इतिहासलेखन "आदिवासियों" के ऑस्ट्रेलियाई निर्माण से शुरू होता है - जो ऑस्ट्रेलिया में गहराई से समस्याग्रस्त है, और भारत में और भी बहुत कुछ है क्योंकि यहां तक कि पूर्वाग्रही रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। भारत - से व्याख्या करने के लिए - ऐतिहासिक रूप से बहुत लंबा है।

उदय चंद्र "ज्वलंत क्षेत्र और जंगल की आग: कृषि परिवर्तन और बिरसा मुंडा के विद्रोह का निर्माण" में, "सहस्राब्दीवाद" की धारणा पर सवाल उठाते हैं जिसे बिरसा मुंडा के "उलगुलान" आंदोलन जैसे आदिवासी आंदोलनों के लिए प्राथमिकता के रूप में लिया गया है। उनका तर्क है कि इस तरह के आंदोलनों के इतिहास पर सहस्राब्दीवाद और एक आवश्यक उपनिवेशवाद-विरोधी रुख थोपा गया है, ताकि ऐसे आंदोलनों के इतिहास को प्रासंगिक और उपयुक्त बनाया जा सके। उनका तर्क है कि जिसे आम तौर पर अब मिशनरियों के रूप में वर्णित किया जाता है" धर्मांतरण के प्रयास ने वास्तव में राजनीतिक सक्रियता के उत्प्रेरक के रूप में काम किया।

संगीता दासगुप्ता ने "मैपिंग हिस्ट्रीज़: टाना पास्ट्स के कई आख्यान" में, उरांव समुदाय के ताना भगतों के जिज्ञासु इतिहास में तल्लीन किया है - कि कैसे जात्रा उरांव ने उनसे उन सभी शारीरिक श्रम को दूर करने का आह्वान किया, जिसमें वे लगे हुए थे, अन्यथा वे करेंगे धर्मेश, उनके देवता द्वारा गूंगा मारा जा सकता है। जात्रा एक गांधीवादी थे, और तानों द्वारा गांधी को एक बाबा माना जाता था - पहिया घूमना और पशु बलि रोकना महत्वपूर्ण मूल्य बन गए। दासगुप्ता का मत है कि ताना इतिहास को केवल तर्कवादी इतिहासकारों के राजनीतिक चश्मे से नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि इसे एक तरल पहचान और धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में भी समझना होगा। ताना के साथ अलग-अलग पहचानें जुड़ी हुई हैं - गांधी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी गाय की रक्षा, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जाति हिंदुओं के खिलाफ प्रतिरोध।

इस विषय पर मौजूदा छात्रवृत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान में, शशांक शेखर सिन्हा ने अपने लेख, "आदिवासी आंदोलन और परे: छोटानागपुर में पितृसत्ता, आधिपत्य और महिला एजेंसी" में प्रमुख आदिवासी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी का पता लगाने की कोशिश की है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान छोटानागपुर। इस तरह के आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी के पैटर्न का अध्ययन करते हुए, लेख इसे आम तौर पर सामाजिक आधिपत्य और पितृसत्ता के प्रमुख प्रवचनों के साथ समझने की कोशिश करता है। महत्वपूर्ण रूप से, वह रोज़मर्रा के प्रतिरोधों की ओर बढ़ते हुए महिलाओं की एजेंसी की एक वैकल्पिक समझ विकसित करने का प्रयास करता है। पूर्व-औपनिवेशिक काल में उत्पादन प्रक्रिया में उनकी स्थिति के महत्वपूर्ण होने से, औपनिवेशिक-पूंजीवादी काल में उनके सापेक्ष हाशिए पर जाने से उनकी "आवाज" के निर्माण और अभिव्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, उनका तर्क है कि तथ्य यह है कि समकालीन समय में महिला आंदोलन कट्टरवाद और गति को बनाए रखने में असमर्थ हैं, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें पूरे युग में उनके कार्यों को रोक दिया गया है और उनकी आवाज को दबा दिया गया है।

संजुक्ता दास गुप्ता ने "आदिवासी पहचान पर पुनर्विचार: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) और सिंहभूम के होस के बीच इसके बाद" में कहा है कि आदिवासी, औपनिवेशिक शासन से पहले भी, जाति समाज से अलग थे और उनकी अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएँ थीं। उन्हें अलग माना जाता था। औपनिवेशिक विमर्श को भी शक्तिशाली जातियों के बीच प्रचलित तत्कालीन मौजूदा अवधारणाओं द्वारा आकार दिया गया था। इसके अलावा, यह तर्क देना कि औपनिवेशिक शासन ने अनिवार्य रूप से गतिशील और असंहिताबद्ध पूर्व-औपनिवेशिक प्रणाली से 'जनजातियों' का आविष्कार किया - न केवल इन समुदायों के जटिल सामाजिक-आर्थिक संगठनों और स्वदेशी संस्थानों के महत्व को नकारता है, बल्कि दीर्घकालिक संरचनात्मक को भी कम करता है। निरंतरता इस तरह का दृष्टिकोण अल्पसंख्यक जातीय समूहों को परंपरा और

सामाजिक प्रथाओं को फिर से आकार देने में उनकी एजेंसी और उनके भाग्य के निर्माण में उनकी अपनी भूमिका से इनकार करता है। दास गुप्ता के लिए दिलचस्प बात यह है कि उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान आदिवासियों के लिए कोई समान विमर्श नहीं था।

जोसेफ बारा ने "एलियन कंस्ट्रक्ट एंड ट्राइबल कॉन्टेस्टेशन इन कोलोनियल छोटानागपुर: द मीडियम ऑफ क्रिश्चियनिटी" में "जनजाति" शब्द के उपयोग और इस तरह की अवधारणा के निर्माण के लिए आदिवासियों की प्रतिक्रिया की जांच की है। उनका तर्क है कि आदिवासी आवाज "दबे हुए सबाल्टर्न या सांस्कृतिक शून्य की चुप्पी" के बजाय "आदिवासी समाज के कुछ जीवंत सांस्कृतिक अंतर्धारा" से आई है। औपनिवेशिक शिक्षा, कानून का ब्रिटिश शासन और ईसाई धर्म ऐसे कारक थे जिनके माध्यम से राज्य ने आदिवासियों को शांत करने का प्रयास किया।

इसने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसके माध्यम से आदिवासियों का सांस्कृतिक शोषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सांस्कृतिक चेतना मजबूत हुई।

इंद्र मुंशी ने अपनी पुस्तक, द आदिवासी प्रश्न: भूमि, वन और आजीविका के मुद्दे में कहा है कि जब आदिवासी हिंदू या ईसाई मूल्यों और प्रथाओं को अपनाते हैं तो वे अपनी आदिवासी पहचान नहीं छोड़ते हैं। आदिवासी धर्म और संस्कृति की संरचना के भीतर नए धर्म के महत्वपूर्ण तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, वह कहती हैं कि राज्य के तत्वावधान में विकास ने राज्य की प्रतिबद्धता के बावजूद आदिवासी संस्कृति (कौशल, भाषा, शासन की संस्थाएं, आदि) का अवमूल्यन और अवमूल्यन किया है।

ईसाई धर्म में रूपांतरण के "विषयों" के उद्देश्यों को विभिन्न लेखकों द्वारा निपटाया गया है, जिनमें से अधिकांश मुंडा और उरांव के बीच ईसाई धर्म में रूपांतरण के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में आर्थिक या भूमि संबंधी प्रोत्साहन पर जोर देते हैं। दोनों, एस.सी.रॉय ने अपने काम द मुंडास एंड देयर कंट्री में, और जॉन मैकडॉगल ने अपने काम लैंड या रिलिजन में भूमि के सवाल और जमींदार के उत्पीड़न से बचने की हताशा पर जोर दिया है, जो आदिवासियों के धर्मांतरण के लिए मुख्य प्रेरक कारक हैं। केएन सहाय ने अपनी पुस्तक अंडर द शैडो ऑफ द क्रॉस में उन कारकों पर विस्तार से चर्चा की है जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार को प्रभावित किया होगा। उन्होंने मुख्य प्रस्तावक होने के नाते जमीन के सवाल पर भी जोर दिया है। धार्मिक और मनोवैज्ञानिक जैसे अन्य उद्देश्यों को सहाय और मैकडॉगल जैसे विद्वानों ने जिम्मेदार ठहराया है। आर.आर. दिवाकर अपनी कृति बिहार थ्रू द एजेस में भी इसी तरह का तर्क देते हैं।

जहां तक धर्मांतरण के एजेंटों के उद्देश्यों और तरीकों का संबंध है, मैकडॉगल और एस.सी.रॉय जैसे विद्वानों में मिशनरियों के इरादों और प्रयासों की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति है। विद्यार्थी जैसे विद्वान; और बी.के.रॉय बर्मन ने अपने काम द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया में, मिशनरियों के तरीकों पर स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया है, जबकि केएन सहाय ने धर्मांतरण में जबरदस्ती की भूमिका पर अधिक स्पष्ट रूप से विस्तार किया है। उद्देश्यों की इस उलझन में ब्रिटिश सरकार की भूमिका एक ऐसा मुद्दा है जिसे अब तक अनदेखा किया गया है। पहले अध्याय में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है।

मुंडा और उरांव के जीवन पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण के प्रभाव पर कई विद्वानों द्वारा चर्चा की गई है। छोटानागपुर में जनजातीय पहचान में बदलाव; और सच्चिदानंद द्वारा जनजातीय बिहार, मुंडा और उरांव में संस्कृति परिवर्तन में। जॉन मैकडॉगल की भूमि या धर्म की तरह काम करता है? बिहार में सरदार और खेरवार आंदोलन 1858-95, एस.सी. रॉय का मुंडा और उनका देश; विद्यार्थी और सहाय की द डायनेमिक्स ऑफ ट्राइबल लीडरशिप इन बिहार ने जमींदारों द्वारा की गई प्रतिक्रिया के संदर्भ में तत्काल परिणाम पर चर्चा की। आदिवासी पहचान और आधुनिक दुनिया में सुरेश शर्मा जैसे विभिन्न विद्वानों द्वारा संस्कृति, शिक्षा और राजनीति के अस्थायी क्षेत्र पर प्रभाव पर चर्चा की गई है; भारत की जनजातीय संस्कृति में एल.पी.विद्यार्थी और बी.के.रॉय; सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में निर्मल मिंज; भारत में जनजातीय अशांति और वानिकी प्रबंधन में रंजीत गुप्ता, जातीयता से क्षेत्रवाद में के.एस.सिंह: 1900 से 1975 तक छोटानागपुर में जनजातीय राजनीति और आंदोलनों में एक अध्ययन, मुंडास और उनके देश में एससीआरॉय, और युग के माध्यम से बिहार में आरआर दिवाकर . हालाँकि, उद्देश्यों को प्रभाव से जोड़ने का प्रयास केवल केएन सहाय द्वारा किया गया है, लेकिन उन्होंने खुद को केवल धार्मिक क्षेत्र के अध्ययन तक ही सीमित रखा है।

2. चुनाव लड़ने की धार्मिक पहचान

यह अध्याय आदिवासियों को उनके संबंधित धार्मिक दायरे में लाने के लिए ईसाई और हिंदू मिशनरियों के तरीकों और उद्देश्यों से संबंधित है। इस अध्याय के पहले भाग में आदिवासियों द्वारा ईसाई मिशनरियों की उनकी गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया के तरीके और उद्देश्यों पर चर्चा की गई है। अध्याय का दूसरा भाग हिंदू मिशनरियों से संबंधित है। छोटानागपुर क्षेत्र में ईसाई और हिंदू दोनों मिशनरियों के इतिहास का पता लगाने के बाद, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म अपनाने के पीछे आदिवासियों के उद्देश्यों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में औपनिवेशिक राज्य की भूमिका को प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आदिवासियों पर मिशनरी गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है और इससे उनकी पहचान में कितना बदलाव आया है।

3. राजनीतिक चेतना का उदय

भारत के अन्य हिस्सों की तरह, छोटानागपुर में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। अन्य क्षेत्रों के विपरीत, इन विद्रोहों का एक अलग चरित्र था। ये विद्रोह न केवल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थे बल्कि गैर-आदिवासियों या दीकुओं के खिलाफ भी थे। इन विद्रोहों में अस्मिता चेतना ने आदिवासियों को बाहरी लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ लामबंद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन्हें गैर-आदिवासी भारतीयों, विशेष रूप से, जमींदारों, साहूकारों और बिहार और बंगाल के व्यापारियों के साथ-साथ औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ एकता की भावना दी। उरांव और मुंडा के कुछ वर्ग स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए और भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ हाथ मिलाते हुए ब्रिटिश शासन के

www.ignited.in

खिलाफ लड़े। कुछ आदिवासी भारतीय और औपनिवेशिक शोषकों दोनों के खिलाफ एकजुट हुए और अपने स्वयं के राष्ट्रवाद के लिए लड़े।

सिंह के. एस. के अनुसार, "कुल मिलाकर आदिवासी लोग अलग-थलग और पिछड़े थे, और हरिजनों के विपरीत, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भागीदारी असंगत थी। वे लगभग अंतिम भारतीय समुदाय थे जिनका राजनीतिकरण किया गया। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन में अनुसंधान, जो हाल ही में क्षेत्रीय आंदोलनों की सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया गया है, ने क्षेत्रीय राजनीति में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के एक समृद्ध पैटर्न का खुलासा किया है। साक्ष्य बताते हैं कि अन्य समुदायों की तरह, आदिवासी समूहों ने स्थानीय राजनीति में तीव्रता से भाग लिया, लेकिन एक अंतर के साथ। आदिवासी समुदाय की ओर से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रणालियों में एकीकरण की तलाश करने और अपनी पहचान को बनाए रखने का प्रयास किया गया था। "

4. विकास के मुद्दों की आदिवासी धारणा और विकास की राजनीति

इस अध्याय की शुरुआत जावेद आलम द्वारा अपने लेख 'फ्रैगमेंटेड कल्चर एंड स्ट्रेंजुलेटेड एक्सिस्टेंस: झारखंडज कल्चरल एनकाउंटर विद द मॉडर्न' में सुनाई गई कहानी से होती है। एक दूरदराज के गांव में जहां लोगों (लगभग सभी आदिवासियों) को जंगल से इकट्ठा किए गए सामान को बेचने के लिए सभ्यता के नाम से अपने पहले संपर्क के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, सरकार ने इस गांव को एक सड़क प्रदान करने का फैसला किया। जैसे ही सर्वेक्षण दल क्षेत्र में पहुंचा, उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसे खदेड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद सर्वेक्षण दल कुछ पुलिस सुरक्षा के साथ वापस आता है और आदिवासियों के साथ कुछ दंगों के बाद इसे एक बार फिर से वापस लेना पड़ता है। बाद में, सर्वेक्षण टीम में एक जिज्ञासु इंजीनियर, जो सड़क बनाने से इनकार करने के लिए बहुत उत्सुक महसूस कर रहा था, ने ग्रामीणों की इस अकर्मण्यता के बारे में बातचीत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए खुद को लिया। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने जो पाया वह काफी दिलचस्प है।

5. आदिवासी राजनीतिक संरचनाओं और अलग राज्य के निर्माण

झारखंड आंदोलन को दक्षिण बिहार की आदिवासी आबादी के लंबे समय से शोषण के खिलाफ असंतोष के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभ में, यह शिक्षित ईसाई आदिवासियों के एक समूह द्वारा आयोजित किया गया था। विरोध दीकुओं के खिलाफ था, जिन्हें वे (आदिवासी) शोषक मानते थे। क्षेत्र के आदिवासियों ने खुद को छोटानागपुर के मूल निवासी के रूप में दावा किया। आर्थिक और राजनीतिक अन्याय आंदोलन का मुख्य कारण था। अतः आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सभी प्रकार के सामाजिक-आर्थिक शोषण को समाप्त करना था। उसी पर चर्चा करते हुए, झारखंड के प्रमुख बुद्धिजीवी और अलग राज्य के समर्थक राम दयाल मुंडा ने एक बार कहा था कि "आंदोलन का उद्देश्य क्षेत्र को शोषकों, साहूकारों, भ्रष्ट नौकरशाहों और निहित स्वार्थों के चंगुल से मुक्त करना है"।

झारखंड के नेताओं के मन में यह था कि अलग राज्य के निर्माण के बिना आर्थिक और सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इन्हें प्राप्त करने के लिए झारखंड राज्य की मांग अपरिहार्य थी। अलग राज्य के आंदोलन के नेताओं का मानना था कि केवल एक नया अलग राज्य जो आदिवासी पहचान पर आधारित होगा, क्षेत्र की स्वदेशी आबादी को सर्वांगीण विकास प्रदान करेगा। उनका मानना था कि मूल निवासियों को अपना स्वामी बनाकर और उनकी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करके ही क्षेत्र के हर क्षेत्र में विकास संभव है। क्षेत्र के आदिवासी नेताओं ने क्षेत्र के " स्वदेशी आदिवासी लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए आत्मनिर्णय के सामूहिक अधिकार" की मांग की। इसलिए अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को राजनीतिक आत्म-पुष्टि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो क्षेत्र के गैर-आदिवासियों के प्रमुख समूह को चुनौती प्रदान करता है। उत्तर-पूर्वी आदिवासी आंदोलन के विपरीत, झारखंड आंदोलन कभी भी गैर के गरीब वर्ग के खिलाफ नहीं था। - आदिवासी समाज। उत्पीड़ित पहचान की राजनीतिक चेतना ने शायद उस समय आंदोलन को समर्थन का आधार प्रदान किया जब जातीय पहचान की राजनीति क्षेत्रीय पहचान की राजनीति में बदल रही थी।

6. निष्कर्ष

मिशनरी छोटानागपुर में दिखाई दिए, जब आदिवासियों को जमींदारों और साहूकारों के शोषण और शोषण के खिलाफ अपने संघर्ष में समर्थन और नेतृत्व की सख्त जरूरत थी। भूमि अधिकारों पर संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसे उन्होंने तुरंत उठाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास नहीं किया था, जैसा कि विभिन्न विद्रोहों से अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात् 1831 में महान कोल विद्रोह, भूमिज के गंगा नारायण विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, पलामू में भोगता का उदय और 1857 के विद्रोह में लोकप्रिय विद्रोह। इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों की हत्या हुई और उनके खिलाफ कड़े कानून पारित किए गए। इसलिए, वे अब किसी भी तिनके को पकड़ने के लिए तैयार थे जो उन्हें उनके दुख से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करेगा। आदिवासियों के ईसाई धर्म अपनाने के उद्देश्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि मिशनरियों में अधिकारियों को उनकी शिकायतों पर ध्यान देने की एकमात्र आशा थी। अवचेतन रूप से शायद उन्होंने यह भी महसूस किया कि यदि वे ईसाईयों के रूप में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनके पास औपनिवेशिक राज्य के लिए मिशनरियों की कथित निकटता के कारण एक बेहतर मौका था। इस प्रकार, यह किसी भी

आध्यात्मिक आवश्यकता के बजाय भौतिक था जो लगता है कि ईसाई धर्म को अपनाने में प्रमुख प्रेरक रहा है।

आदिवासियों के बीच ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरियों द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे वास्तव में बाद की स्थिति को बेहतर बनाने में रुचि रखते थे। उन्होंने न केवल कानूनी उपाय दिए, जो लंबे समय में प्रतिरोध का एक उपकरण साबित हुआ, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशनरी धर्मार्थ गतिविधियों ने आदिवासियों की बहुत मदद की। हालांकि, वे धर्मान्तरित लोगों को जीतने के लिए झूठे वादे करने के अलावा धमकी और जबरदस्ती का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उनका ध्यान न केवल आदिवासियों के आध्यात्मिक उत्थान पर था, बल्कि ईसाई धर्म की तहों के भीतर उनके औपचारिक प्रेरण और प्रतिधारण पर भी था, जिसके लिए वे इस उद्देश्य के लिए भौतिक प्रलोभन या बल का उपयोग करने के लिए तैयार थे। वे अपने हस्तक्षेप के लाभार्थियों को चुनने में भी चयनात्मक थे। इस प्रकार, ईसाई धर्म ने आदिवासियों को प्रभावित करने के तरीके में इन विधियों की एक सहवर्ती भूमिका होना तय था क्योंकि तरीकों का ध्यान आध्यात्मिक क्षेत्र के बजाय लौकिक पर अधिक था।

7. ग्रन्थसूची

1. ब्रॉकिंगटन, जॉन, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, लंदन, 1992
2. बिहार नोट्स: आदिवासियों के साथ, महात्मा गांधी के एकत्रित कार्य, XXVIII,
3. बर्गस्ट्रॉम, लार्स, (1990) 1993, ग्रुंडबोक आई वर्डेटियोरी, बोकफोर्लगेट थेल्स।
4. बूर, विवियन, (1995) 2000, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, रूटलेज, पैडस्टो, यूके बटलर, ऑक्टेविया ई., 1993, पैरेल ऑफ़ द सॉवर, सेवन स्टोरीज़ प्रेस, न्यूयॉर्क;
5. 1961 की जनगणना रिपोर्ट, बिहार खंड, भाग V-A
6. संविधान सभा वाद-विवाद, खंड 9, 24 अगस्त 1949,
7. ईसाई मिशनरियों के साथ चर्चा, 6 जनवरी 1940, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़
8. महात्मा गांधी, एलएक्सएक्सआई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार
9. भारत, 1978
10. भारतीय सांविधिक आयोग की रिपोर्ट 1930
11. अंतरिम रिपोर्ट, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों पर संयुक्त उप-समिति (अन्य असम से), 1947:9
12. डॉ. जॉन मोट का साक्षात्कार, महात्मा गांधी का एकत्रित कार्य, एक्स्ट्रा लार्ज, मंत्रालय सूचना और प्रसारण, भारत सरकार, 1970
13. राजेंद्र प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू का पत्र, 10 अगस्त, 1953, की चयनित रचनाएँ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी श्रृंखला, खंड-23, जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष जवाहरलाल नेहरू, "द ट्राइबल फोक", (भाषण के उद्घाटन सत्र में दिया गया)
14. वेस्टन, एंथोनी, 1995, "पर्यावरणीय नैतिकता से पहले," ओल्स्च्लेगर में, 1995।
15. वेस्ट्रा, लौरा, 1989, "पारिस्थितिकी और पशु: क्या सम्मान की एक संयुक्त नैतिकता है? में, पर्यावरण नैतिकता, वॉल्यूम। 11, नंबर 3, 1989।
16. व्हाइट, लिन जूनियर, 1967, "हमारे पारिस्थितिक संकट की ऐतिहासिक जड़ें," विज्ञान में, वॉल्यूम। 155, संख्या 3767, (मार्च) 1967।
17. विटोसजेक और ई. गुलब्रांडसन, (सं.), 1993, संस्कृति और पर्यावरण, अंतःविषय दृष्टिकोण, विकास और पर्यावरण केंद्र, प्रौद्योगिकी और संस्कृति केंद्र, ओस्लो विश्वविद्यालय, ओस्लो।
18. यंग, आइरिस मैरियन, 1990, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन।
19. रुएथर, रोज़मेरी रैडफोर्ड, 1975ए, "महिलाएं, पारिस्थितिकी, और प्रभुत्व" नेचर, "द इक्यूमेनिस्ट में, 14, 1975।
20. रुएथर, रोज़मेरी रैडफोर्ड, 1993, गैया एंड गॉड: एन इकोफेमिनिस्ट थियोलॉजी ऑफ़ अर्थ हीलिंग, एससीएम प्रेस लिमिटेड, लंदन।

Corresponding Author

सबिता कुमारी*

www.ignited.in